



समझौता ज्ञापन

वित्तीय वर्ष 2026-27

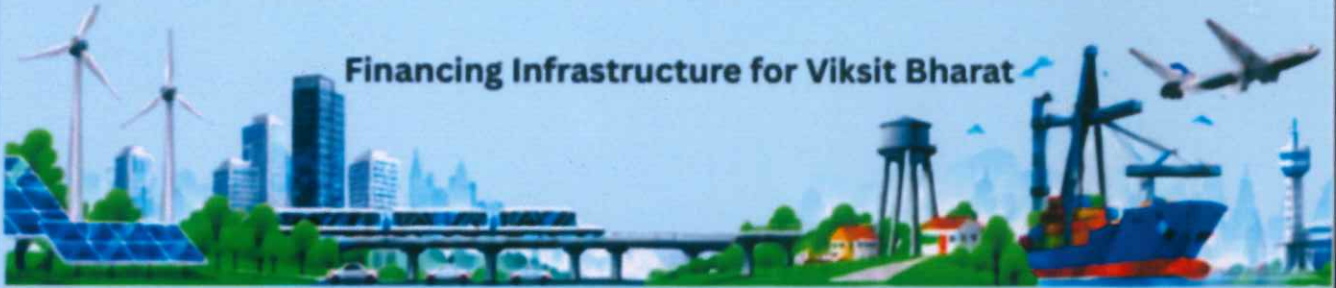
MoU

FY 2026-27

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

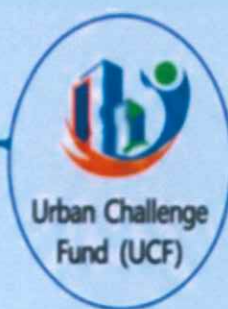
Housing and Urban Development Corporation Limited

Financing Infrastructure for Viksit Bharat



शहरी विकास विभाग, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

**Department of Urban Development, Ministry of Housing
and Urban Affairs Government of India**



HUDCO BHAWAN, CORE 7-A, INDIA HABITAT CENTRE, LODHI ROAD, NEW DELHI - 110003

हडको भवन कोर-7-ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

MoU for the year 2026-27	
CPSE and Administrative Ministry/Department	
Housing and Urban Development Corporation Ltd.	Department of Urban Development, Ministry of Housing & Urban Affairs

Scope : Consolidated

Objectives, Responsibilities and Governing Framework:

As prescribed vide DPE's MoU framework for performance evaluation of the CPSEs.

Parameter-wise annual targets for the year 2026-27

Part-I : Main Parameters

S.No.	Parameter	Unit	Wt.	Target 2026-27
1	Revenue from Operations	₹ Crore	15	16500
2	Loan Disbursed to Total Fund Available	%	10	100.00
3	Overdue Loans to Total Loans	%	10	1.51
4	NPA to Total Loans	%	10	0.05
5	Cost of Raising funds through bonds as compared to similarly rated CPSEs	BPS	8	-8.20
6.	Block for Admin Ministry Priorities		5	As per Annexure-A
7.	EBTDA (as a percentage of Total Income)	%	8	30.00
8.	Return on Net Worth	%	10	15.05
9.	Return on Capital Employed	%	5	10.50
10.	Asset Turnover Ratio	%	4	10.50
11.	Total Return to Shareholders	%	10	100.00
12.	Dividend Payout	%	5	100.00
Total			100	

MoU for the year 2026-27

Part-II : Compliance Parameters

S.No.	Parameter	Marks	Source/ Verification
1	DPE guidelines on CSR expenditure	-1	
2	Provisions in the Companies Act, 2013 [or SEBI (LODR) regulations in case of listed entities] on Corporate Governance: a. Composition of Board of Directors b. Board Committees c. Holding Board and Committees' Meetings d. Related Party Transactions e. Disclosures and Transparency	-3.0 (0.60 for each)	
3	Onboarding of CPSE on all operational TReDS platforms	-1.0	
4	Timely payments to MSE vendors as prescribed in MSMED Act	-3.0 (graded)	
5	Procurement of goods and services (as % of total procurement), from: a. MSEs overall – 25% b. SC/ST owned MSEs – 4% c. Women owned MSEs – 3%	-2.0 (0.66 for each)	
6	Succession Planning and Leadership Development Plan	-1.0	
7	Surplus non-core assets (land & building) monetization plan.	-1.0	
8	Adoption of emerging technologies Plan	-1.0	

MoU for the year 2026-27

Annexure A

Notes:

- a) Main parameters including Administrative Ministry Priorities (unless otherwise specified), shall be evaluated on a proportionate marking basis for achievements ranging between 50% and 100% of the target and the achievements below 50% of the target shall score zero, except in the case of the Total Return to Shareholders parameter.
- b) There shall be no adjustment in prescribed targets or achievements on account of changes in exchange rates, regulatory prices of raw materials or finished goods, reduction in margins, or any other reason, as these are considered normal business conditions, unless otherwise specified.
- c) The aggregate score shall be contingent upon compliance with the prescribed compliance parameters. Failure to comply shall result in the deduction of full marks, as indicated, without any partial or proportionate deduction, unless otherwise specified.
- d) When calculating annual achievements, any quantified qualifications from the Comptroller and Auditor General (C&AG) or Statutory Auditors would be adjusted accordingly in the Revenue, Profit, Surplus, etc.
- e) The specific targets are not prescribed in the MoU for: (i) Total Return to Shareholders, if applicable and (ii) Dividend Payout. These parameters shall be evaluated based on achievements against prescribed benchmarks, as per the methodology contained in the MoU Guidelines, at the closing of the financial year.

MoU for the year 2026-27

Administrative Ministry Priorities

S.No.	Parameter	Unit	Weightage	Target
1.	Roll-out of Board-approved Operational Guidelines for financing to State entities, PPPs at competitive pricing for UCF Projects	Date	2	30.06.2026
2.	Loan Sanctioned for Projects under UCF	₹ Crore	3	10,000

Reference:

- IMC Minutes dated 18.08.2026
- MoHUA OM No. A-42012(16)/1/2025-AA-MoHUA dated 10.06.2026



Sh. Sanjay Kulshrestha,
Chairman and Managing Director
Housing and Urban Development
Corporation Limited

Date:



Sh. Satendra Singh,
Secretary,
Ministry of Housing & Urban Affairs
Government of India

Date:

वर्ष 2026-27 हेतु समझौता ज्ञापन	
सीपीएसई और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	
हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शहरी विकास विभाग , आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

स्कोप: समेकित

उद्देश्य, उत्तरदायित्व और गवर्निंग फ्रेमवर्क:

जैसा कि सीपीएसई के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन हेतु डीपीई के समझौता ज्ञापन फ्रेमवर्क में निर्धारित है।

वर्ष 2026-27 हेतु मापदण्ड-वार वार्षिक लक्ष्य

भाग- I: मुख्य मापदण्ड

क्र.सं.	मापदण्ड	इकाई	अंक	लक्ष्य 2026-27
1.	प्रचालन से राजस्व	₹ करोड़	15	16500
2.	कुल उपलब्ध निधियों के सापेक्ष संवितरित ऋण	%	10	100.00
3.	कुल ऋणों के सापेक्ष अतिदेय ऋण	%	10	1.51
4.	कुल ऋणों के सापेक्ष एनपीए	%	10	0.05
5.	समरूप रेटिंग वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संस्थाओं की तुलना में बॉन्ड्स के माध्यम से निधि अर्जित करने की लागत	बीपीएस	8	-8.20
6.	प्रशासनिक मंत्रालय की प्राथमिकताओं हेतु ब्लाक		5	अनुलग्नक क अनुसार
7.	ईबीटीडीए (कुल आय के प्रतिशत के रूप में)	%	8	30.00
8.	निवल मूल्य पर प्राप्ति	%	10	15.05
9.	नियोजित पूंजी पर प्राप्ति	%	5	10.50
10.	परिसंपत्ति कारोबार अनुपात	%	4	10.50
11.	शेयरधारकों को कुल रिटर्न	%	10	100.00
12.	लाभांश भुगतान	%	5	100.00
कुल			100	

वर्ष 2026-27 हेतु समझौता ज्ञापन

भाग- II: अनुपालन मापदण्ड

क्र.सं.	मापदण्ड	अंक	स्रोत/सत्यापन
1	सीएसआर व्यय पर डीपीई दिशानिर्देश	- 1.0	
2	कॉर्पोरेट संचालन पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों [अथवा सूचीबद्ध इकाइयों के मामले में सेबी (एलओडीआर) विनियम]: क. निदेशक मंडल का संयोजन ख. बोर्ड समितियाँ ग. बोर्ड और समितियों की बैठकें आयोजित करना घ. संबंधित पक्ष लेनदेन ड. प्रकटीकरण और पारदर्शिता	- 3.0 (0.60 प्रत्येक के लिए)	
3	सभी परिचालन टीआरईडीएस प्लेटफार्मों पर सीपीएसई को शामिल करना	- 1.0	
4	एमएसएमईडी अधिनियम में निर्धारित एमएसई विक्रेताओं को समयोचित भुगतान	- 3.0 (श्रेणीबद्ध)	
5	निम्नलिखित से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद (कुल खरीद का %) क. समग्र एमएसईएस - 25% ख. एससी/एसटी स्वामित्व वाले एमएसईएस - 4% ग. महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसईएस - 3%	- 2.0 (0.66 प्रत्येक के लिए)	
6	लीडरशिप डेवलपमेंट प्लान	- 1.0	
7	अधिशेष गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों (भूमि एवं भवन) मुद्रीकरण योजना।	- 1.0	
8	उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने की योजना	- 1.0	

वर्ष 2026-27 हेतु समझौता ज्ञापन

अनुलग्नक क

टिप्पणी :

- (i) क) प्रशासनिक मंत्रालय की प्राथमिकताओं (जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो) सहित मुख्य मापदंडों का मूल्यांकन लक्ष्य के 50% से 100% के बीच की उपलब्धियों के लिए आनुपातिक अंकन के आधार पर किया जाएगा और लक्ष्य के 50% से नीचे की उपलब्धियों को, शेयरधारकों के कुल रिटर्न पैरामीटर के मामले को छोड़कर शून्य स्कोर दिया जाएगा।
- (ii) विनिमय दरों में बदलाव, कच्चे माल या तैयार माल की नियामक कीमतों, मार्जिन में कमी, या किसी अन्य कारण से निर्धारित लक्ष्यों या उपलब्धियों में कोई समायोजन नहीं होगा, क्योंकि इन्हें सामान्य व्यावसायिक स्थितियां माना जाता है, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।
- (iii) समग्र अंक अनुपालन मापदंडों को पूरा करने पर निर्भर होंगे। अनुपालन न करने पर, बिना किसी आंशिक या आनुपातिक कटौती के, दर्शाए गए अनुसार (जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो) पूर्ण अंक काट लिए जाएंगे।
- (iv) वार्षिक उपलब्धियों की गणना करते समय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) या वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई किसी भी परिमाणित अर्हता को राजस्व, लाभ, अधिशेष आदि में तदनुसार समायोजित किया जाएगा।
- (v) MoU में निम्नलिखित के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं: (i) शेयरधारकों को कुल प्रतिफल, यदि लागू हो और (ii) लाभांश भुगतान। इन मानदंडों का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष के समापन पर, MoU दिशानिर्देशों में निहित कार्यप्रणाली के अनुसार, निर्धारित बेंचमार्क के मुकाबले उपलब्धियों के आधार पर किया जाएगा।

वर्ष 2026-27 हेतु समझौता ज्ञापन

प्रशासनिक मंत्रालय की प्राथमिकतायें

क्र.सं.	मापदण्ड	इकाई	अंक	लक्ष्य 2026-27
1.	राज्य संस्थाओं, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण पर PPPs को UCF परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण हेतु बोर्ड-अनुमोदित परिचालन दिशानिर्देशों को जारी करना	तिथि	2	30.06.2026
2.	यूसीएफ के तहत परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृति	₹ करोड़	3	10,000

सन्दर्भ :

- IMC मिनट्स दिनांक 18.08.2026
- MoHUA OM No. A-42012(16)/1/2025-AA-MoHUA दिनांक 10.06.2026

सं. जय कुलश्रेष्ठ

श्री संजय कुलश्रेष्ठ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

दिनांक

सतेन्द्र सिंह

श्री सतेन्द्र सिंह
सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय,
भारत सरकार

दिनांक